

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :-463 / 2025

अमृता शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, अराजपत्रित एवं अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, पंचायतीराज चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक नर्सिंग अधिकारी, नवीन चिकित्सा मेडिकल कॉलेज, कोटा।
4. रूपेश कुमार नागर, नर्सिंग अधिकारी, सीएचसी, मांगरोल, बारां।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की तिथि : 11.02.2025

आदेश की दिनांक : 12.02.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भावला, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर नवीन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज कोटा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांगरोल जिला बारां में करीब 100 किमी दूर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के विरुद्ध है। अपीलार्थी परित्यक्ता महिला कार्मिक है। अपीलार्थी पर उसकी वृद्ध माता एवं बीमार भ्राता आश्रित है। अपीलार्थी का

भाई गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने से वह चलने फिरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है (अनुलग्नक-3)। माता एवं भाई की देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को नर्सिंग अधिकारी के पद पर नवीन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज कोटा में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य